



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 114]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 4, 2010/वैशाख 14, 1932

No. 114]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 4, 2010/VAISAKHA 14, 1932

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मई, 2010

फा. सं. 12012/1/2009-एस आर (पार्ट-1) — जबकि 9 दिसम्बर, 2009 और 23 दिसम्बर, 2009 को दिए गए वक्तव्यों तथा 5 जनवरी, 2010 को आंध्र प्रदेश के मान्यताप्राप्त आठ राजनैतिक दलों के साथ हुई बैठक के अनुसरण में, भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश में सभी वर्ग के लोगों तथा सभी राजनैतिक दलों और समूहों से विस्तृत विचार-विमर्श करने के लिए 3 फरवरी, 2010 से 'आंध्र प्रदेश की स्थिति पर विचार-विमर्श करने के लिए समिति (सी सी एस ए पी)' के नाम से निम्नलिखित व्यक्तियों को शामिल करके एक समिति का गठन किया :

- |   |             |
|---|-------------|
| (1) श्री न्यायमूर्ति बी. एन. श्रीकृष्ण,<br>सेवानिवृत्त न्यायाधीश, भारत<br>का उच्चतम न्यायालय                          | —अध्यक्ष    |
| (2) प्रोफेसर (डॉ.) रणबीर सिंह, कुलपति,<br>राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली  | —सदस्य      |
| (3) डॉ. अबुसलाह शरीफ, वरिष्ठ रिसर्च<br>फेलो, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान<br>संस्थान, दिल्ली                    | —सदस्य      |
| (4) डॉ. (सुश्री) रवीन्द्र कौर, प्रोफेसर,<br>मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विभाग,<br>भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली | —सदस्य      |
| (5) श्री विनोद दुग्गल, आई ए एस<br>(सेवा निवृत्त) पूर्व गृह सचिव   | —सदस्य सचिव |

2. उपर्युक्त समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं :—

(1) पृथक तेलंगाना राज्य की मांग तथा अविभाजित आंध्र प्रदेश की वर्तमान स्थिति को बनाए रखने की मांग के संदर्भ में आंध्र प्रदेश राज्य में व्याप्त स्थिति की जांच करना।

(2) राज्य के गठन के समय से अब तक के घटनाक्रमों की तथा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति और विकास पर इनके प्रभाव की समीक्षा करना।

(3) महिलाओं, छात्रों, अल्पसंख्यकों, अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों जैसे लोगों के विभिन्न वर्गों पर राज्य में हुए हाल के घटनाक्रमों के प्रभाव की जांच करना।

(4) ऊपर मद (1), (2) और (3) में उल्लिखित मामलों पर विचार करते समय उस मुख्य मुद्दे का पता लगाना जिसका समाधान किया जाना जरूरी है।

(5) उपर्युक्त मामलों पर विभिन्न वर्गों के लोगों, विशेष रूप से राजनैतिक दलों के साथ परामर्श करना और उनके विचार प्राप्त करना; राजनैतिक दलों और अन्य संगठनों से बात करके ऐसे समाधान तलाशना जिनसे मौजूदा बदली हुई स्थिति का समाधान हो सके और सभी वर्गों के लोगों के कल्याण को बढ़ावा मिल सके; इस प्रयोजन के लिए वैकल्पिक समाधानों का पता लगाना; और एक कार्य-योजना तथा रोड मैप की सिफारिश करना।

(6) उपर्युक्त मामलों पर उद्योग, व्यापार, ट्रेड यूनियनों, कृषक संगठनों, महिला संगठनों और छात्र संगठनों जैसे समाज के अन्य संगठनों के साथ परामर्श करना और राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के चहुंमुखी विकास के संदर्भ में उनके विचार जानना।

(7) अन्य कोई सुझाव देना अथवा सिफारिश करना, जो समिति को उचित लगे।

3. समिति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए स्वयं की प्रक्रिया का निर्धारण करेगी और समिति, यदि ऐसा करना आवश्यक समझे तो ऐसे मामलों की, ऐसे तरीके से और ऐसे व्यक्तियों द्वारा अन्वेषण अथवा जांच करा सकती है जिसे वह समुचित समझती हो। भारत सरकार के मंत्रालय और विभाग ऐसी सूचना और दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे तथा ऐसी सहायता प्रदान करेंगे जो समय-समय पर समिति द्वारा अपेक्षित होगी।

4. समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

5. समिति अपनी रिपोर्ट 31 दिसम्बर, 2010 तक प्रस्तुत करेगी।

डॉ निर्मलजीत सिंह कलसी, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 4th May, 2010

**F. No. 12012/1/2009-SR (Pt-I).**—Whereas in pursuance to the statements made on 9th December, 2009 and December 23, 2009 and the meeting with the eight recognized political parties of Andhra Pradesh on January 5, 2010, the Government of India constituted the following Committee known as the Committee for consultations on the situation in Andhra Pradesh (CCSAP) from 3rd February, 2010 to hold wide-ranging consultations with all sections of the people and all the political parties and groups in Andhra Pradesh :—

- (1) Shri Justice B.N. Srikrishna, Retired —Chairman  
Judge, Supreme Court of India
- (2) Prof. (Dr.) Ranbir Singh, Vice —Member  
Chancellor, National Law  
University, Delhi
- (3) Dr. Abusalah Shariff, Senior —Member  
Research Fellow, International  
Food Policy Research Institute,  
Delhi
- (4) Dr. (Ms.) Ravinder Kaur, Professor, —Member  
Department of Humanities and  
Social Sciences, IIT, Delhi
- (5) Shri Vinod Duggal, IAS (Retd.), —Member  
Former Home Secretary Secretary

2. The terms of reference of the above Committee are as follows :—

- (1) To examine the situation in the State of Andhra Pradesh with reference to the demand for a sepa-

rate State of Telangana as well as the demand for maintaining the present status of a United Andhra Pradesh.

- (2) To review the developments in the State since its formation and their impact on the progress and development of the different regions of the State.
- (3) To examine the impact of the recent developments in the State on the different sections of the people such as women, students, minorities, other backward classes, scheduled castes and scheduled tribes.
- (4) To identify the key that must be addressed while considering the matters mentioned in items (1), (2) and (3) above.
- (5) To consult all sections of the people, especially the political parties, on the aforesaid matters and elicit their views; to seek from the political parties and other organizations a range of solutions that would resolve the present different situation and promote the welfare of all sections of the people; to identify the optional solutions for this purpose; and to recommend a plan of action and a road map.
- (6) To consult other organizations of civil such as industry, trade, trade unions, farmers' organizations, women's organizations and students' organizations on the aforesaid matters and elicit their view with specific reference to the all round development of the different regions of the State.
- (7) To make any other suggestions or recommendations that the Committee may deem appropriate.

3. The Committee will devise its own procedure for the discharge of its functions, and the Committee may, if it deems it necessary so to do, have investigation or examination of such matters as it may deem fit to be made in such manner and by such persons as it may consider appropriate. The Ministries and Departments of the Government of India shall furnish such information and documents and provide assistance as may be required by the Committee from time to time.

4. The Headquarters of the Committee will be at New Delhi.

5. The Committee shall submit its report by December 31, 2010.

Dr. NIRMALJEET SINGH KALSI, Jt. Secy.